राज्य सभा/लोक सभा की पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज

अधिकृत प्रतिलिपि
Authenticated Copy
(अर्जुन राम मेघवाल)
(ARJUN RAM MEGHWAL)
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
Minister of State (I/C) for Law & Justice and
Minister of State (I/C) for Parliamentary Affairs

प्रमाणीकृत
(अर्जुन राम मेघवाल)
केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 500 करोड़ रुपये से कम के वित्तीय परिव्यय वाली योजनाओं के संबंध में आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क संकेतक

विधि एवं न्याय मंत्रालय — **मांग संख्या-65**

न्याय विभाग

1. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (सीएसएस)

वित्तीय व्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
200	1. लंबित बलात्कार और पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफ़टीएससी) की स्थापना।	1.1 नियोजित एफ़टीएससी में से चालू एफ़टीएससी की संख्या	900	1. लंबित बलात्कार और पॉक्सो एक्ट मामलों का निपटारा	1.1 एफटीएससी द्वारा पंजीकृत कुल मामलों में से निपटाए गए बलात्कार के मामलों का प्रतिशत।	100
					1.2 एफ़टीएससी द्वारा कुल रजिस्टर्ड मामलों की तुलना में पोक्सो एक्ट मामलों का निपटारा किए गए मामलों का प्रतिशत।	100

वित्तीय व्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
					1.3 प्रति न्यायालय मामलों का औसत मासिक निपटान	9

नोट: एफ़टीएससी योजना को दिनांक 31.3.2026 से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

2. डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेज़ टु जस्टिस इन इंडिया (दिशा) (सीएस)

वित्तीय व्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
59.4#	(क) **टेली लॉ: वंचितों तक पहुँच**					
	1. टेली-लॉ के तहत ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए मुकदमा पूर्व सलाह और कानूनी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना	1.1 सीएससी, मोबाइल एप्लीकेशन, न्याय सहायकों और टेली लॉ हेल्पलाइन के माध्यम से दी गई सलाह की संख्या	50,00,000	1.जमीनी स्तर पर लोगों के लिए टेली-लॉ के माध्यम से मुकदमेबाजी से पहले (प्री-लिटिगेशन) की सलाह तक पहुंच में सुधार करना।	1.1 पिछले वर्ष की तुलना में कानूनी सलाह प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	30,00,000
		1.2 टेली-लॉ पर प्रशिक्षित ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई), न्याय सहायकों, राज्य समन्वयकों और टेली-लॉ कॉलर्स की संख्या	1,00,000			
		1.3 नियुक्त किए जाने वाले पैनल वकीलों की संख्या (संचयी)	1,000			
	(ख) **न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम**					

वित्तीय व्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	1. निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए वकीलों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना	1.1 पंजीकृत किए गए निःशुल्क वकीलों की संख्या	1,000	1.जमीनी स्तर पर लोगों के लिए टेली-लॉ के माध्यम से मुकदमेबाजी से पहले (प्री-लिटिगेशन) की सलाह तक पहुंच में सुधार करना।	1.1 निःशुल्क कानूनी सेवाओं के अंतर्गत पंजीकृत वकीलों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि	10
	2. प्रोबोनो वकीलों के माध्यम कानूनी सहायता या सलाह को बढ़ावा देना	2.1 टेली-लॉ के तहत कानूनी सहायता/सलाह प्रदान करने वाले प्रो-बोनो अधिवक्ताओं की संख्या	800		1.2 लाभार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि	10,00,000
	3. विधि विद्यालयों में प्रो-बोनों क्लबों की उप-योजना (सब-स्कीम) को सुविधाजनक बनाना	3.1 विधि महाविद्यालयों की संख्या जहां प्रो-बोनो क्लब उप योजना (सब-स्कीम) को कार्यान्वित किया जाना है।	60			
	(ग) **कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम**					
	1. कानूनी जानकारी और अधिकारों तक बेहतर पहुंच	1.1 कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लाभार्थियों की संख्या	20,00,000	1. कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता में सुधार	1.1 कानूनी साक्षरता और जागरूकता में सुधार लाने के लिए जिन लोगों तक पहुंचा गया, उनकी संख्या में प्रतिशत परिवर्तन।	10
		1.2 शामिल किए जाने वाले कार्यान्वयन साझेदारों/एजेंसियों की संख्या	11			
	(घ) **विधि संजीवनी- आउटरीच और संचार**					
	1. दिशा (DISHA) योजना और इसके घटकों तक पहुंच में वृद्धि	1.1 मानकीकृत कानूनी ज्ञान उत्पादों (वीडियो, कॉमिक्स, टूलकिट, लघु फिल्में आदि) के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली कानूनी जागरूकता के लाभार्थियों की संख्या।	20,00,000	1. सूचना विषमता और भ्रामक/गलत सूचना को कम करना	1.1 ऑनलाइन विजिट करने और फीडबैक सबमिट करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या।	30,000

वित्तीय व्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
		1.2 अलग-अलग हितधारकों के लिए किए गए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की संख्या (ऑफ़लाइन/ऑनलाइन)	40			
	2. बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन	2.1 केंद्रीय एमआईएस और डिजिटल डैशबोर्ड को गतिविधियों पर आधारित बनाया जाएगा।	1			

वित्तीय वर्ष -2026-27 के लिए वित्तीय व्यय एसएफ़सी के हिसाब से 59.40 करोड़ रुपए रखा गया था। हालांकि, www.indiabudget.gov.in के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में DISHA योजना के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

3. कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) (सीएस)[4]

वित्तीय व्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
300##	1. एलएडीसीएस में योग्य डिफेंस काउंसल को शामिल किया गया।	1.1 आपराधिक मामलों के लिए एलएडीसीएस में शामिल किए गए बचाव वकीलों की संख्या	9,243	1. एलएडीसीएस मामलों में उच्च निपटान	1.1 पिछले वर्ष की तुलना में एलएडीसी द्वारा निपटाए गए मामलों	5

वित्तीय व्यय (रुपये करोड़ में)	आउटपुट 2026-27			आउटकम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	2. सभी आपराधिक न्यायालयों में मुकदमों और अपीलों का प्रतिनिधित्व/संचालन करना, जिसमें सभी प्रकार के विविध कार्य शामिल हैं।	2.1 जमानत/रिमांड संबंधी कार्यों के अतिरिक्त आपराधिक मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व, सलाह या सेवाएं प्रदान किए गए मामलों की संख्या	2,03,624		की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन[14]	
		2.2 जमानत/रिमांड संबंधी आपराधिक मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व, सलाह या सेवाएं प्रदान किए गए मामलों की संख्या	3,82,032	2. आपराधिक मामलों में किफायती कानूनी सहायता बचाव	2.1 पिछले वर्ष की तुलना में एलएडीसी द्वारा निपटाए गए प्रति मामले की औसत लागत में प्रतिशत परिवर्तन[7]	2.5
	3. जिलों की जेलों का समय-समय पर दौरा	3.1 जेलों के किए गए दौरों की संख्या	42,660			

www.indiabudget.gov.in के अनुसार एलएडीसीएस स्कीम का फ़ाइनेंशियल खर्च 300 करोड़ रुपये है। लेकिन, ईएफ़सी मेमो के ड्राफ़्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फ़ाइनेंशियल खर्च 558.87 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

1 निपटाए गए रेप केस का प्रतिशत = (वर्ष के दौरान एफ़टीएससी द्वारा निपटाए गए रेप केस की संख्या/वर्ष के दौरान एफ़टीएससी के साथ रजिस्टर्ड रेप केस की कुल संख्या) x 100
2 निपटाए गए पोक्सो केस का प्रतिशत = (वर्ष के दौरान एफ़टीएससी द्वारा निपटाए गए पोक्सो एक्ट केस की संख्या/वर्ष के दौरान एफ़टीएससी के साथ रजिस्टर्ड पोक्सो एक्ट केस की कुल संख्या) x 100
3 हर कोर्ट में औसत मंथली निपटारा = वर्ष के दौरान एफ़टीएससी द्वारा निपटाए गए केस की कुल संख्या (कार्य कर रहे एफ़टीएससी की संख्या x 12)
4 यह ड्राफ़्ट वर्शन है क्योंकि एलएडीसीएस स्कीम का ईएफ़सी मेमोरेंडम विचाराधीन है।
5 वर्ष 2025-26 के लिए टारगेट की गणना इस आधार पर की गई थी कि 703 एलएडीसीएस ऑफिस में से हर एक में 10 डिफेंस काउंसल। यह देखते हुए कि पिछले साल 7,030 (703*10) डिफेंस काउंसल पहले ही ऑनबोर्ड हो चुके थे, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल टारगेट 711 एलएडीसीएस ऑफिस में से हर एक में 13 डिफेंस काउंसल के आधार पर 9243 (711*13) अपडेट किया गया है।